







# जबरन वापसी

**य**ह विडंबना ही है कि पूरे विश्व को लोकतांत्रिक मूल्यों, मानव अधिकारों व आदर्श जीवन मूल्यों की नसीहत देने वाले अमेरिका ने विभिन्न देशों के कथित अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने की कार्रवाई को बलपूर्वक अंजाम दिया है। सुनहरे सपनों की आस में धर-खेत दांव पर लगाकर व एजेंटों को लाखों रुपये देकर अमेरिका पहुँचे युवाओं ने सपने में नहीं सोचा होगा कि उहें अपराधियों की तरह वापस उनके देश भेजा जाएगा। ये हमारे नीति-नियंत्राओं की विफलता ही है कि

सुनहरे सपनों की आस  
में घर-खेत दांव पर  
लगाकर व एजेंटों को  
लाखों रुपये देकर  
अमेरिका पहुंचे युगाओं  
ने सपने में नहीं सोचा  
होगा कि उन्हें

अपराधियों की तरह  
वापस उनके देश भेजा  
जाएगा। ये हमारे नीति-  
नियंताओं की विफलता  
ही है कि हमारी युगा  
शक्ति दुनिया के  
विभिन्न देशों में लुट-  
पिटकर अपमानजनक  
स्थितियों का सामना  
कर रही है। कभी उन्हें  
पूर्ण एशिया के देशों में  
साइबर अपराधी बंधक  
बनाकर ऑनलाइन  
घोखाधड़ी को अंजाम  
देते हैं, तो कभी उन्हें  
घोखे से बिचौलिए रुसी  
सेना में भर्ती करवा देते  
हैं। कभी उन्हें इसाइल-  
हमास के भयावह  
युद्धग्रस्त इलाके में  
काम की तलाश में  
पहुंचा दिया जाता है।

अपने भटके हुए नागरिकों की वैध भारत ने समझदारी से टकराव टालने पर की मुलाकात से पहले दोनों देशों चय ही तुनक मिजाज ट्रूप व उनके दोई समझदारी भी नहीं थी। ऐसी ही दोनों पेट्रो द्वारा अपने प्रवासी नागरिकों की उत्तरण देने की घोषणा करके अपने दीर्घी थी। पहले उन्होंने निर्वासित लोगों वीकार करने से मना कर दिया था। या पर रैरिफ और प्रतिबंध लगाने की गा। अब वही कोलंबिया के राष्ट्रपति 'जिक संपदा' के निर्माण में योगदान ल उठाता है कि क्या भारत के पास अपने करीब अटठारह हजार कथित को लेकर कोई योजना है? सरकार ये लोग फिर किसी आप्रवासन का समय की मांग है कि बेइमान ट्रैवल ई की जाए, जो युवाओं को सुनहरे व अन्य देशों में भेजते हैं।

# ए मध्यम क

---

आठवें बजट के बारे  
लाख रुपये तक की  
इसमें कोई संदेह नहीं  
से बहुत बड़ी छलांग  
। लेकिन एक तरह से  
या त्वं अशाश्वा मे

धरेलु पाने वाले अपनारों से 12 लाख रुपये से एक आय से आगे कर की 12 लाख रुपये की आय को 4 लाख रुपये से 5प्रतिशत की दर से बढ़ावा देते हुए कि 12 लाख रुपये का छूट मिलेगा, सवाल है कि देखते हुए, वर्तमान भूगतान से छूट लाख करोड़ रुपये से ज़रूर का बजट कहा जा सकता है और निजी क्षेत्र बजट रुद्धिवादी लगता है जिसमें प्रतिक्रिया में इंडियन और मांग को देखने शुरू में ही अपना विकास को गति देने, जिसे क्षेत्र के निवाश को उठाने और भारत के विकास को बढ़ाने के लिए लघु और मांग को लघु और मांग को पक्ष अर्थशास्त्रीय राष्ट्रपति रोना चाहिए पेशकश की अपेक्षा और अमेरिका के छूट में उछाल दिया गया है। क्या

# मोहन के जापान दौरे से मप्र के औद्योगिक विकास को मिली नई दिशा

हर्षवर्धन पाण्डे

**म**ध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जापान यात्रा ने न केवल जापान की औद्योगिक प्रगति और विकास को करीब से समझने का अवसर प्रदान किया बल्कि वहां के लोगों की जीवनशैली, संस्कृति, तकनीकी विकास को भी करीब से देखा। जापान सरकार और प्रवासी भारतीयों द्वारा डॉ. यादव का गर्मजाशी से स्वागत किया गया। जापान में उनकी यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश और जापान के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना रहा। जब वह टोक्यो पहुँचे तो उनका बहां स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल हुए। टोक्यो में जापान के निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों और संभावनाओं के विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव 'फ्रेंड्स ऑफ एमपी-जापान' टीम के साथ भेंट करने के साथ ही टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औद्योगिक और निवेश सहयोग के विषय पर बैठक की जिसके बाद टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में 'सेलिब्रेटिंग इंडिया-जापान रिलेशनशिप : फोकस मध्यप्रदेश' रोड्शो में भी सहभागिता की। जापान के तकनीकी विकास से डॉ. मोहन यादव को काफी प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे जापान अपने अत्यधिनिक तकनीकी अविष्कारों और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। वहाँ की रेल प्रणाली ने उन्हें खासा प्रभावित किया। उन्होंने बुलेट ट्रेन की सवारी की और महसूस किया कि कैसे यह तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सबसे तेज और सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान एक्स्टर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के साथ टोक्यो के मिनाटो-कू में विस्तृत चर्चा की जिसमें जापानी कंपनियों के मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर संभावनाओं और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विवरण हुआ। जेट्रो ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ बड़े निवेश पर चर्चा की। डॉ. मोहन यादव ने जापान इंटरनेशनल कॉऑपरेशन एजेंसी को मध्यप्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने वाली कंपनी एपनडीडी मेडिकल के निदेशक डाइकी अराई ने मध्य प्रदेश में निर्माण इकाई स्थापित करने की मंशा जाहिर की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टोक्यो में एपनडी मेडिकल कम्पनी के निदेशक डाइकी अराई से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में चिकित्सा उपकरण निर्माण के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन के अत्यधिनिक मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिये आमंत्रित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों का रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करा रही है। उन्होंने इस पार्क को भारत के तेजी से विकसित हो रहे हेल्थ केयर और

जापान के तकनीकी विकास से डॉ. मोहन यादव को काफी प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे जापान अपने अत्याधुनिक तकनीकी अविष्कारों और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। वहाँ की रेल प्रणाली ने उन्हें खासा प्रभावित किया। उन्होंने बुलेट ट्रेन की सवारी की और महसूस किया कि कैसे यह तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सबसे तेज और सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के साथ टोक्यो के मिनाटो-कू में विस्तृत चर्चा की जिसमें जापानी कंपनियों के मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर संभावनाओं और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। जेट्रो ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ बड़े निवेश पर चर्चा की।

मेडिकल डिवाइस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बताया। उज्जैन में बन रहे मेडिकल डिवाइस और मुख्य रूप से मेडिकल सेक्टर के लिए भी जापान के उद्योगपतियों से निवेश की बात कही है। सीएम डॉ. यादव के प्रयासों से मध्य प्रदेश में मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चरिंग का नया हब बनने जा रहा है जिसके लिए जापान से निवेशकों के बड़े प्रस्ताव भी मिले हैं। उन्होंने सेसमेक्स की अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइस निर्माण तकनीक का अवलोकन किया और मध्यप्रदेश में सिसमेक्स को आमंत्रित किया। एंडडी मेडिकल ने प्रथम प्रदेश में अपनी निर्माण इकाई स्थापित करने में विशेष रुचि दिखाते हुए उन्होंने वर्ष के अंत तक इसे शुरू करने की बात कही है। जापान की एंडडी मेडिकल कम्पनी वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य निगरानी उत्पादों का उत्पादन करती है। डॉ. मोहन यादव ने कोबे और ओसाका में स्थैत हेल्थ केयर और डॉयग्नोस्टिक कम्पनी साइसमेक्स प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों के उद्योगपतियों के साथ बैठक की और हेल्थ केयर, ऊर्जा और पैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश एवं साझेदारी पर भी चर्चा की। उन्होंने जापानी कार निर्माता कंपनी 'टोयोटा मोटर कार्पोरेशन' के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर उनसे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। पैनासोनिक एनर्जी कंपनी लिमिटेड, डॉयग्नोस्टिक कंपनी साइसमेक्स पहिल कई औद्योगिक कंपनियों ने बैटरी निर्माण और प्रदेश में ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई और मध्य प्रदेश में भरपूर निवेश का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जापान दौरे में प्रवासी भारतीयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने जो नींव तैयार की है उसका फायदा भारत की आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। जापान की यात्रा डॉ. मोहन यादव के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। जापान में डॉ. यादव की सादरी लोगों के देल में उत्तर गई। डॉ. यादव ने अपने सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो खूब बायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके सहज, सरल और आकर्षक व्यक्तित्व की विलक्षण छाप देखने को मिल रही है। लोग जापानी अंदाज और भाषा में उन्हें विदाई दे रहे हैं। इम्प्रियल होटल से चेक-आउट करते समय होटल के सदस्यों ने बड़ी देरतक खड़े होकर उनके लिए तालियां बर्जाई और तस्वीरें खिंचवाई। लोग तब तक होटल के मुख्य द्वारा पाँखड़े रहे, जब तक डॉ. यादव कार में नहीं बैठे। मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होगा औन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 15,000 से अधिक निवेशकों के शामिल होने की उमीद है। यह सम्मेलन उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख द्वितीय बाजार होगा। इस बार की समिट में जापान कंट्री पार्टनर होगा जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। जापानी निवेशकों के अलावा अन्य देशों के भी निवेशक इस समिट में भाग लेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी। इस आयोजन से नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और राज्य की औद्योगिक छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उमीद है। उन्होंने कहा जा सकता है कि डॉ. मोहन यादव का जापान दौरा एम्पी में जापानी कंपनियों के बीच निवेश को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुआ है। उन्होंने अपनी चार दिन की जापान यात्रा में न केवल जापान के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की और निवेश और व्यापार के नए अवसरों को तराशा बल्कि जापानी समाज और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। उन्होंने वहां की तकनीकी प्रगति, कला, संस्कृति और व्यापारिक दृष्टिकोण को अपनी यात्रा के अनुभवों में समाहित किया। यह यात्रा मध्य प्रदेश और जापान के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी सहायक साबित हुई है।

है। पिछले महाकुंभ आयोजनों में देखा गया था कि संगमरम्भ और अन्य घाटों के आसपास प्लास्टिक की बोतलों और अन्य कचरे की समस्या गंभीर रूप से बढ़ जाती थी। इसका बार प्रशासन ने न केवल स्वच्छ जलपूर्ति की व्यवस्था करने है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है कि वाटर एटीएम पूरे आयोजन के दौरान बिना किसी बाधा के कार्य करते रहें। इसके अलावा प्रयागराज प्रशासन आगे भी इसकी तरह की पहल करने पर विचार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ श्रद्धालुओं को तो मिल ही रहा है, इससे प्रशासन को पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में भी सफलता मिल रही है। यह प्रयोग श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बन गया है। यह प्रयोग एतिहासिक और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। वाटर एटीएम का विचार नया नहीं है। सुरक्षित पेयजल की चुनौती को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक समाधान के रूप में वाटर एटीएम और जल शुद्धिकरण यंत्र जैसे छोटे जल उद्यमों को मान्यता देने की शुरू की है। सेफ वॉटर नेटवर्क के अनुसार, देश में सामुदायिक जलसोधन संयंत्रों की संख्या वर्ष 2014 में 12,000 थी। यह 2018 में बढ़कर लगभग 50,000 हो चुकी है। वर्तमान में यह संख्या और ज्यादा होगी। सरकार 2030 तक हर घर जल के अंतर्गत तेजी से काम कर रही है। देश के लाखों लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम की शुरूआत 2008 में पीरामल फाउंडेशन के सेल्स हेड धर्मवीर सिंह ने की थी। उन्होंने इसके लिए सर्वजल अभियान शुरू किया था। यह वाटर एटीएम वाटर बूथ भी कहलाते हैं। जैसे की मिल्क बूथ होते हैं जो दूध उपलब्ध कराते हैं और ये वाटर बूथ पानी उपलब्ध कराते हैं। ये वाटर बूथ दिखने में एटीएम की तरफ होते हैं, इसलिए इन्हें वाटर एटीएम भी कहा जाता है।

# प्रधानमंत्री महाकुम्भ में वाटर एटोएम को सफलता के माध्यम

गें बाज

वाटर एटीएम के माध्यम से निःशुल्क पेयजल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। पहले यह सुविधा एक रूपये प्रति लीटर के शुल्क पर उपलब्ध थी। तब श्रद्धालु या तो सिकंका डालकर या यूपीआई स्कैन के माध्यम से भुगतान कर आरओ जल प्राप्त कर सकते थे। अब यह सेवा पूरतरह निःशुल्क है। इसके मकसद यह है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। यही नहीं प्रत्येक वाटर एटीएम पर एक ऑपरेटर तैनात किया गया है। वह श्रद्धालुओं के अनुरोध पर बटन दबाते ही शुद्ध जल उपलब्ध कराता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को जल प्राप्त करने में कोई समस्या न हो और पेयजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे। महाकुंभ में स्थापित वाटर एटीएम आधुनिक तकनीक से लैस है। इन मशीनों में सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली लगी हुई है, जो किसी भी तकनीकी खामी का तुरंत पता लगाती है। यदि किसी वाटर एटीएम में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे जल निगम के तकनीशियन तुरंत ठीक कर देते हैं।

आधुनिक तकनीक से लैस है। इन मशीनों में सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली लगी हुई है, जो किसी भी तकनीकी खामी का तुरंत पता लगाती है। यदि किसी वाटर एटीएम में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे जल गम के तकनीशियन तुरंत ठीक कर देते हैं। महाकुंभ ला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की विशाल संख्या को देखते हुए येक वाटर एटीएम से प्रतिदिन 12 से 15 हजार लीटर

आरओ जल की आपूर्ति की जा रही है। सभी वाटर एमें सिम-आधारित तकनीक का प्रयोग किया गया है वजह से यह प्रशासन के केंद्रीय नेटवर्क से जुड़े रहता है। इस तकनीक के जरिये कुल जल खपत, जलस्तर प्रबंधन जल की गुणवत्ता और वितरण की मात्रा पर नियंत्रण रखी जाती है। हर बार जब कोई श्रद्धालु वाटर एटीएम उपयोग करता है तो एक लीटर शुद्ध जल निकलता है,

काशिंश को गयी है। घरेलू उत्पाद के लिए, बजट घरेलू मांग का सूजन पर अपनी उम्मीदें टिकाये हुए हैं, जो अकेले ही न नये निर्जन क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दे सकता है। आखिरकार, अगर राजकोषीय घाटे को बनाये रखना है, तो सरकारी खर्च में वृद्धि नहीं हो सकती। बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं या अन्य सार्वजनिक निवेशों में बड़े सार्वजनिक निवेश की घोषणा नहीं की गयी है। सरकार घरेलू विनिर्माण में एक बड़ा कदम उठाने की उम्मीद कर रही है जो अब तक साकार नहीं हुआ है। इसके बजाय, बजट अब विनिर्माण की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने के लिए छोटे और मध्यम क्षेत्र के मजबूत करने और अधिक रोजगार सूजन गतिविधियों की ओर अग्रसर है। बजट कम से कम उस दृष्टिकोण को दर्शाने के प्रयास करता है। हालांकि, ब्लॉक में एक नया बच्चा तथाकथित श्माईयूलर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इस प्रयास में निजी क्षेत्र की भागीदारी है। वह मोलर परमाणु संयंत्रों में अधिक उदासीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संकेत दे रही है। छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रमुख खिलाड़ी हो सकते हैं। यदि भारत को कृतिमान बुद्धिमत्ता में अगे बढ़ाना है तो यह एक निर्णायक कारक हो सकता है। बिजली की आसान उपलब्धता के आधार पर एआई विकसित हो सकता है। सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पर भरोसा कर रही है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश काफी अग्रणी बढ़ाना जरूरी था। परन्तु सरकार ने बुनियादी ढांचे में बड़े सार्वजनिक निवेश की घोषणा करने में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4प्रतिशत पर रखा है, जबकि बजट अनुमान 4.8प्रतिशत था। यह मुख्य रूप से जी-एसटी संग्रह में उछाल के कारण संभव हो सकता है। इस तरह के नियंत्रित घाटे से निजी क्षेत्र को धन जुटाने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। अंत में, हर बजट बड़ी घोषणा वाल नहीं हो सकता। यह बजट छोटे-छोटे कदमों के

निम्न और मध्यम वर्ग को सिफे कर में छूट देना मांग को बढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं

8

**व** त मत्रा निमला सातारमण के आठव बजट के बार में एकमात्र बड़ा विचार 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 7 लाख रुपये की छूट सीमा से बहुत बड़ी छलांग है। हालांकि इसमें एक राजनीतिक पेंच है। लेकिन एक तरह से यह दिल्ली बिजली शुल्क के बारे में आप की अवधारणा से उत्तराधिकारी लिया गया है। यानी, अगर आय 12 लाख रुपये से एक रुपया ज्यादा है, तो 4 लाख रुपये की आय से आगे कर की प्रगतिशील दर लागू होगी। मान लीजिए, 12 लाख रुपये की आय में एक रुपया और जोड़ने पर, व्यक्ति को 4 लाख रुपये से ज्यादा की आय प्रा-प्रगतिशील पैमाने पर 5प्रतिशत की दर से कर देना होगा। संभवतरू, यह उमीद करते हुए कि 12 लाख

बजट ने लघु और मध्यम क्षेत्र को महत्व दिया है। यह सर्वोत्कृष्ट आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तब था जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकियों को बड़े कर कटौती की पेशकश की थी और वे मांग में भारी उछाल के साथ वापस आये और अमेरिकी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर, छूट में उछाल को छोड़कर, कराधान दरों को अछूता छोड़ दिया गया है। क्या निम्न और मध्यम वर्ग के लिए आयकर रियायत समग्र घरेलू मांग को बढ़ावा देगी और भारत को आगामी ट्रम्प स्टॉर्म टैरिफ और एक अशांत वैश्विक अर्थव्यवस्था से पार पाने में मदद करेगी? 31 जनवरी को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में, यह सवाल उठाया गया था और इसका उत्तर मांगा गया था। सर्वेक्षण ने तर्क दिया था कि वैश्विक स्थिति बिगड़ रही है या कम से कम वैश्वीकरण पीछे हट रहा है। इसलिए, घरेलू मांग को और बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। भारत मुख्य रूप से घरेलू मांग के दम पर बढ़ रहा है।

नहा मिल पाइ ह। साथ हा, वित मत्रा न भारत क नियत हिता का रक्षा करन का काशश का ह

के निवेश पर जोर देता है। कुल मिलाकर बजट रुद्धिवादी लगता है। बयानबाजी की कमी शेराव बाजार की धीमी प्रतिक्रिया में दबलकरती है। उन्होंने लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग को महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में देखा था। उन्होंने शुरू में ही अपना मूल उद्देश्य बताते हुए कहा था-यह बजट विकास को गति देने, समावेशी विकास को सुरक्षित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घेरू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए लघु और मात्र लघु और मात्र पक्ष अर्थशास्त्र राष्ट्रपति रोने पेशकश की और अमेरिका छूट में उछाल गया है। क्या

गयु और मध्यम उद्यमशीलता की उम्मीद कर रही थी। बजट ने गयु और मध्यम क्षेत्र को महत्व दिया है। यह सर्वोक्तुष्ट आपूर्ति क्षम अर्थसास्त्र है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तब था जब प्रृष्ठपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकियों को बड़े कर कटौती की शक्ष की थी और वे मांग में भरी उछाल के साथ वापस आये और अमेरिकी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर, इट में उछाल को छोड़कर, कराधान दरों को अचूता छोड़ दिया गया है। क्या निम्न और मध्यम वर्ग के लिए आयकर रियायत में दबद त सवाल उ ने तक वैश्वीकरण देने की उपर बड़े उम्मीद है। अब तक

? 31 जनवरी को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में, यह गया था और इसका उत्तर मांगा गया था। सर्वेक्षण का कि वैश्विक स्थिति बिगड़ रही है या कम से कम हट रहा है। इसलिए, घरेलू मांग को और बढ़ावा यकृता थी। भारत मुख्य रूप से घरेलू मांग के दम परियोजनाओं और प्रस्तावों की पुनरावृत्ति की तरह लग रहा अतिशयोक्ति न करते हुए, अंततः यह फायदेमंद भी हो सकता है। कैसे? वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को विकास के पहले के रूप में महत्व दिया है। वित्त मंत्री ने मूल्यवर्धित कृषि







